

MR SPEAKER : Possibly I had not made myself clear on that point I am clarifying the matter.

So far as permission given in a particular matter is concerned, no other person can revise it because the permission has been already given by the presiding officer

So far as the ruling is concerned, in that particular case that ruling is binding. Another person cannot revise it. But the Speaker may not take it as a precedent for other cases but in that particular case he cannot revise the ruling because it is binding

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : On a point of order. We are discussing the White Paper on Monday, and that White Paper is based on the Report of the Dass Committee. We have received a copy of the White Paper, but we have not received a copy of the Report of the Dass Committee. So, may I request you to ask the Government to supply us a copy of the Dass Committee's Report?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : We discussed it in the Business Advisory Committee and if I remember a right, we were assured that the Dass Committee's Report would be made available in sufficient numbers. If it has not been done, it should be done now.

MR SPEAKER : We have already written to the Ministry for the Dass Committee's Report, and we are hoping to get it. As soon as we get it, we will distribute it.

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar) : By tomorrow.

MR SPEAKER : On Monday.

PROF P G MAVALANKAR : If we do not get the Report by tomorrow, how are we to speak on Monday?

MR SPEAKER : We will try to get it.

PROF P G MAVALANKAR : By tomorrow afternoon at least.

श्री जयसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, बहम के पहले दास नमंटी की रिपोर्ट अगर कन मिल जाये तो हम लोग पढ़ कर उस को तैयार करेंगे।

MR SPEAKER : Calling Attention. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav

SHRI JYOTIRMOY BOSU : When are you giving me permission?

MR SPEAKER : I have already called Mr Yadav

Shri Jyotirmoy Bosu : I would like to know, sir, that I can be present.

MR SPEAKER : About what?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : About the notice under 377 that I have given.

MR SPEAKER : That will be tomorrow, not today.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Why not today?

MR SPEAKER : Not today.

12 36 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Apprehension of damage to North Eastern railway line due to soil erosion.

श्री जयेश्वर प्रसाद यादव (जयगिया) अध्यक्ष महोदय, मैं भविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की श्री रेल मन्त्री का ध्यान दिलाना और श्री प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में मगर वक्तव्य दें

“निकट भविष्य में गंगा नदी से भूमि के कटाव के कारण नारायणपुर और बाहपुर के बीच पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य लाइन की क्षति की आशंका के समाचार।”

रेलमंत्री (प्रो० मधु बंडवते) महोदय, मैं मदन को सूचित करना चाहूँगा कि नारायणपुर रेलवे स्टेशन के निकट गंगा नदी के बाएँ किनारे पर हो रहे कटाव से उत्पन्न खतरे की रेलवे को जानकारी है। कटाव और अधिक न होने पाये इसलिए नदी सुरक्षा सम्बन्धी व्यापक निर्माण-कार्यों की आवश्यकता है और राज्य सरकार द्वारा उन निर्माण-कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

नारायणपुर रेलवे स्टेशन के निकट गंगा नदी द्वारा किये जा रहे कटाव पर रेले काफी असुर में बड़ी सावधानीपूर्वक निगाह रख रही हैं। गंगा नदी नियन्त्रण आयोग और राज्य सरकार के साथ अप्रैल 1976 के दौरान हुई एक बैठक में, रेलवे ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि नदी द्वारा किये जा रहे कटाव की रोकथाम नहीं की गयी तो रेल लाइन को

गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप रेलवे के लिए यह आवश्यक हो जायेगा कि वर्तमान लाइन को वहा से हटा कर कहीं अन्यत्र बनाया जाय। उस बैठक के दौरान, राज्य सरकार ने हमें हम वा। से अवगत कराया था कि वे 1976 की वर्षा ऋतु से पहले कुछ तटबन्धों का निर्माण कार्य पूरा कर रहे हैं जिनसे नागयणपुर रेलवे स्टेशन तथा रेलवे लाइन का बचाव हो जायेगा। उपर्युक्त तटबन्धों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के बावजूद, 1976 की बाढ़ से और कटाव हाता रहा है और नदी किनारा काट कर रेलवे लाइन में 287 मीटर (940 फुट) की दूरी तक आ पहुची जबकि 1973 में यह दूरी 1730 मीटर (5676 फुट) थी। अक्टूबर, 1976 में आयी बाढ़ के तुरन्त बाद, राज्य सरकार तथा गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के साथ हुई दूसरी बैठक में, रेलवे ने कटाव निरोधी उपायों की तुरन्त व्यवस्था करके रेलवे लाइन और नागयणपुर रेलवे स्टेशन को बचाने की बात पर अधिक जोर दिया। रेल मन्त्रालय ने अपनी यह उच्छा भी व्यक्त कर दी थी कि वह कटाव निरोधी कार्यो पर होने वाले खर्च की अन्य सम्बन्धित पार्टियों, अर्थात् बिहार राज्य सरकार, परिवहन मन्त्रालय और भारतीय तेल निगम, के साथ बराबर-बराबर वहन करने के लिए तैयार है और राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि वह इस काम को शीघ्र शुरु कर दे और इसे 1977 की वर्षा ऋतु से पहले-पहले पूरा कर दे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा गया।

राज्य सरकार ने 5-5-1977 को इस काम को शुरु करने और इसे बिहार राज्य निर्माण निगम को सौंपने का विनिश्चय किया। तब से ही काम शीघ्र समाप्त करने के लिए रेल प्रशासन राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा बिहार राज्य निर्माण

निगम को माल डिब्बों की सप्लाई और सामान के शीघ्र संचलन के मामले से सभी सम्भव सहायता/सहयोग दे रहा है।

नदी के किनारे का लगभग 2000 फुट भाग ऐसा है जिसे नदी से खतरा रहता है। इस अत्यधिक भेद भाग में कटाव निरोधी उपाय बरतने सम्बन्धी काम का पहला चरण बिहार राज्य निर्माण निगम ने मई/जून, 1977 में शुरु किया था। यह आशा थी कि यह कार्य पिछले महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा। लेकिन पानी के मामान्य स्तर से ऊपर चढ़ने (9-7-1977 और 19-7-1977 के बीच 11 फुट से अधिक) के कारण आगे काम रोक दिया गया था। यदि नदी का कटाव रेलवे लाइन अथवा नागयणपुर टाउन के निकट आ जाता है तो ऐसी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए 2 लाख घन फुट पत्थर का स्टॉक तैयार रखने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि नदी के जिस किनारे को खतरा पैदा हो गया है, उसे मुदद बनाये रखने के लिये सभी सम्भव उपाय करें। काम पूरा होने तक राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जायेगा।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव . अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे लाइन के ऊपर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है और इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है कि 1973 में भी इस बात की आर ध्यान दिनाया गया था लेकिन बाढ़ नियंत्रण आयोग ने इस प्रकार का विश्वास दिलाया कि गंगा के कटाव से बचाने के लिए हमने योजना स्वीकार की है जिससे बाढ़ और कटाव की समस्या दूर हो जाएगी। 1973-74 में मैंने ही लोक सभा में यह प्रश्न किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खगरिया से लेकर कटिहार तक गंगा तटबन्ध से होकर रेलवे लाइन गुजरती है और रेलवे लाइन की मुख्य धारा जो पहले

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

उत्तर-दक्षिण की तरफ थी, मुंघेर, भागलपुर हो कर बहती थी, वह अब भागलपुर, मुंघेर को छोड़ कर उत्तर की ओर बढ़ती जा रही है, जिस के कारण खगनिया से ले कर कटिहार तक पिछले तीन-चार दिनों में रेलवे लाइन, आसाम रोम और तेल पाइपलाइन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सिंचाई विभाग से मिल कर कोई इस प्रकार की योजना तैयार करेंगे कि गंगा की मुख्य धारा मुंघेर से सट कर चण्डी स्थान और भागलपुर हो कर बहे, ताकि जो उत्तरी भाग कट रहा है, वह बच सके? आप ने मानसी में तीन करोड़ रुपया खर्च किया और अब नारायणपुर में खर्चा कर रहे हैं, बार-बार आपको खर्चा करना पड़ रहा है—इसलिए मैं जानना चाहता हूँ—क्या आप केन्द्रीय सरकार के सिंचाई विभाग के साथ मिल कर कोई इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आगे किसी प्रकार का खतरा पैदा न हों?

दूसरा प्रश्न—क्या रेल विभाग के पास सक्षम इंजीनियर नहीं थे, जिस के कारण बिहार के सिंचाई विभाग के द्वारा आप कार्य को करा रहे हैं? वहाँ के सिंचाई विभाग ने मानसी में जो काम किया, उसके थोड़े और छ टाँघार के बारे में सब को मालूम है। मानसी बचाव की योजना में उक्त अधिकारियों ने जो अष्टा-घार और गोलमाल किया, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए गोताखोर ने उस का पता लगाया है और पेट्रीशन्स कमेटी में भी इस मामले की छानबीन की है। वहाँ के इंजीनियरों ने अष्ट तरीके से करोड़ों रुपये की राशि कमाई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवृत्त करना चाहता हूँ—आप के पास सक्षम इंजीनियर हैं, जिन्होंने कोसी में इस प्रकार का काम किया है, वहाँ की रेलवे लाइन और पुल की बचाया है इसलिए क्या आप अपने इंजीनियरों की सहायता से उस काम को पूरा करायेंगे? गंगा की डूरी अब केवल 460 फुट रह गई है।

मैं चाहूँगा कि आप इस और तुरन्त ध्यान दें। और उन अष्ट लोगों से मुक्ति दिलायें।

तीसरा प्रश्न—फलडू कंट्रोल विभाग ने इस काम का ठेका कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को दिया है। बिहार के भूतपूर्व सिंचाई मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने अपने सम्बन्धियों के खाने-पीने और मीज करने के लिए कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का निर्माण किया था और आज उस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। मैं 30-6-1977 की राति को, जब मुझे कटाव के बारे में टेलीग्राम मिला, सीधा वहाँ गया, कोई भी इंजीनियर वहाँ स्पॉट पर नहीं था। मैं 11 बजे से 2 बजे राति तक वहाँ रहा, केवल दो ओवरसीयर जो कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन और फलडू कंट्रोल के थे, वहाँ पर थे। कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने उस काम के लिए पेट्री-कॉन्ट्रैक्ट्स को नियुक्त किया है। आप को चाहिए था कि आप सीधे फलडू-कंट्रोल द्वारा काम कराते या रेलवे के इंजीनियरों से काम कराते। आप ने स्वयं स्वीकार किया है कि दो हजार फुट ऐसी जगह थी, जहाँ कटाव था। मैंने स्वयं उस दिन देखा कि एक हजार फुट में कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने अपने ठेकेदारों से काम कराया, लेकिन उसमें भी क्रेटिंग और बोल्डस 20 फुट नदी की सतह तक डालना चाहिए था, वे केवल 10 फुट और एक फुट ऊँचाई तक डाला गया और 40 फुट का जो स्लोप तैयार करना चाहिए था—बॉल्डर-पांचिंग ने लिए, उस में कमी रह गई। एक हजार फुट में तो नहीं के बराबर काम हुआ। जब पानी आ गया, कटाव हो गया, तो तार की जितनी जालियाँ थी, सब को नदी में बसा दिया गया ताकि नाजायज ढंग से पैसा ले सकें। इस काम में केवल आप का पैसा

मिला है, परिवहन मंत्रालय, भारतीय तेल निगम और बिहार सरकार ने पैसा नहीं दिया है। इसलिए मंत्री महोदय से मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ कि आप अपने विभाग के सक्षम इंजीनियरों से इस काम को कराये। बिहार सरकार से आप सहायता लें, लेकिन बिहार सरकार के उन अग्रस्त इंजीनियरों को न ले, जिन्होंने मानसी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इस प्रकार का अपराध आप से है।

प्रो० मधु षण्डवते : मान्यवर, माननीय सदस्य ने तीन-चार सवाल उठाये हैं। सबसे पहले मैं उन को जानकारी देना चाहता हूँ—इस काम की मूलतः या बुनियादी जिम्मेदारी रेलवे की न होने हुए भी हम लोगों ने देखा कि जो बटाव बढ़ता जा रहा है, उस से ज्यादा तकलीफ रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन और नजदीक के गांवों को होने वाली है। इसलिए हम लोगों का इस सवाल की तरफ देखने का रवैया यह है कि रेलवेज, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री-क्योंकि इन्डियन आयल का सवाल आता है—और साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट और बिहार गवर्नमेंट, इन सब के सहयोग से इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। हम किसी एजेंसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन मूलतः यह जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है फिर भी हमारा जो फर्ज है, उस को हम भरा करने के लिए तैयार हैं और जो भी जानकारी हमारे पास है, वह मैंने पहले अपने बयान में वे दी है। मैं यह भी आप को बता दूँ कि जब हम लोगों ने गंगा पलड कन्ट्रोल कमीशन के साथ बात की थी, उसी वक्त उन को बताया था कि हमें धारणा है कि इस से इरोजन बढ़ता रहेगा। मैं यह भी आप को बताना चाहता हूँ कि कन्ट्रोल कमीशन

की तरफ से जून, 1977 में काम शुरू हुआ और उस ने उस वक्त वहाँ पर स्टोन-ट्रक्चर जिस को हिन्दी में 'स्पर्स' (spursh) कहते हैं, बनाने का काम शुरू किया लेकिन जब 9 जुलाई, से 19 जुलाई, तक और उस के बाद बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के बाद सब स्पर्स भी बह कर चले गये। इसलिए रेलवे ने यह मुझसे कहा था कि आगे चल कर हम को ज्यादा एम्बैकमेन्ट बनाने होंगे और उस के लिए ज्यादा सहयोग देने की बात हम ने तय की लेकिन जब तक बाढ़ का पानी बहा रहेगा, काम शुरू नहीं हो सकता। उस के लिए एक दूसरा विकल्प यह भी है कि आगे चल कर एक डार्डवर्जरी रूट बनाई जाये और वह 11 किलोमीटर का रूट होगा। इस को बनाने में हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उस के लिए हमें ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन गांव के लोगों की, किसानों की लेनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे लोग गरीब हैं और हम से उन की जमीन चनी जाएगी और दूसरा काम यह होगा कि हाईवे की तरफ और दूसरे देहातों की तरफ अगर पानी जाएगा, तो उन को तकलीफ होगी। इसलिए जो एम्बैकमेन्ट की बात है, उसी पर वे जोर देना चाहते हैं और मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो चार एजेंसियां हैं, उस में रेलवे के इंजीनियर के सहयोग का जो मुझसे दिया गया है, उस के अनुसार हमारा पूरा सहयोग रहेगा और इस काम को हम पूरा करेंगे और बाढ़ के कारण जो देहातवालों को नुकसान होता है, हम कोशिश करेंगे कि वह न हो।

हम लोगों ने यह भी कहा कि गंगा की धारा में परिवर्तन करें लेकिन गंगा के स्तर के बढ़ने का जो काम है, वह

[श्री० मधु दण्डवते]

हम लोगों के लिए कोई प्रासान काम नहीं होगा। इस में एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होगी और प्रायोग के जो एक्सपर्ट है और इरीगेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे और जो भी उन की सलाह होगी, उस के मुताबिक काम किया जाएगा।

जहाँ तक खर्च का सवाल है, चारो एजेन्सियों के काम करने की बात बहुत अच्छी है लेकिन इन चारो एजेन्सियों में सिर्फ रेलवे ही एक ऐसी एजेन्सी रही है, जिस ने अपना हिस्सा चकता किया है। इससे पता चलता है कि रेलवे का कारोबार बहुत अच्छा रहता है और इस बात का सबूत भी आज डम सदन में मिला है। मैं यह आश्वासन सदन में देना चाहता हूँ कि आगे भी हमारे अच्छे कार्य का सबूत आप को मिलता रहेगा चारो एजेन्सियों के सहयोग में डम सवाल को हल करने की हम कोशिश करेंगे यह आश्वासन मैं आप के जरिए सदन को देना चाहता हूँ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : बाढ़ के पहले इस पर कितना खर्च हुआ है ?

प्रो० मधु दण्डवते : 1 2 करोड़ रुपए।

12.48 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

Alleged misleading information given by the Minister of Home Affairs re. Belchi Incident

MR. SPEAKER : Yesterday Sarvashri C.K. Chandrappan and B. Rachiah sought to raise a question of privilege regarding alleged misleading information given to the House on the 13th June, 1977, in the statement made by the Minister of Home Affairs on a calling attention matter about atrocities on Harijans at Belchi village in Bihar. Some members stated that the Deputy Speaker had given his consent to raise this matter under rule 222.

I then observed that the records did not show that the Deputy Speaker has given his permission under rule 222. In fact, what the Deputy Speaker had said in the House on the 16th July, 1977, was :

"In accordance with the practice of the House in such matters, I have sent copies of the notices to the Minister of Home Affairs for his factual comments. I will take a decision in the matter after I receive a reply from the Home Minister."

The observations of the Deputy-Speaker were communicated in writing to Sarvashri C.K. Chandrappan, K.A. Rajan, B.P. Kadam and Shrimati Parvathi Krishnan on the 16th July, 1977, itself.

The Lok Sabha Bulletin-Part I dated the 16th July, 1977, also contains an entry to this effect on this matter.

However, I observed yesterday that I would consult the Deputy-Speaker whether he had given his permission to his matter being raised under rule 222 as claimed by certain Members. The Deputy-Speaker has informed me in categorical terms that he had not given permission to any Member under rule 222 to raise this matter in the House.

It is thus clear that the contention of these Members that the Deputy-Speaker had given them permission to raise this matter under rule 222 is not correct. I have already disallowed this matter as stated earlier on the ground that the question relating to motive for the occurrence is *sub-judice*.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : On a point of order. You have been pleased to observe...

श्री इयाम सुन्दर बास (मीतामढी) : अध्यक्ष महोदय, आपने गृह मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को अस्वीकृत कर दिया है। अब सवाल यह है कि माननीय सदस्यों ने जो गलत आरोप लगाया है और हाउस को मिसनीड किया है, क्या उनके विरुद्ध प्रिविलेज का मोशन आ सकता है या नहीं ?

MR. SPEAKER : There is no point of order. Please sit down. Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE : You have been pleased to observe yesterday and just now that you have not given permission because the matter is *sub-judice*. I would only like to know as a matter of